

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 251/2021

कैलाश पुत्री पृथ्वीराज पत्नी महावीर जाति जाट निवासी ताखरांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।



बनाम

1. निमा देवी पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 3 के. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. अशोक कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 3 के. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. बिमला पुत्री पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 3 के. मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. उर्मिला पुत्री पृथ्वीराज पत्नी लालचन्द जाति जाट निवासी ख्यालीवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. सुमन पुत्री पृथ्वीराज पत्नी हरीराम जाति जाट निवासी हरियासर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
6. संतोष पुत्री पृथ्वीराज पत्नी महावीर जाति जाट निवासी चुनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील सूरतगढ जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोंडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश सहायक कलक्टर पीलीबंगा, दिनांक 21.12.2021, प्र. सं. 82/

अनवान कैलाश बनाम निमा देवी आदि



*karis*  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़

## उपस्थिति:-

श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक अपीलार्थी,  
श्री विजय कौशिक, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1  
श्री लोकेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोंडेंट सं० 2, 3, 5, 6  
श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्टा ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रार्थना-पत्र की मद संख्या 4 में वणित भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जस प्रार्थी का धरू बंटवारा के समय से ही हक व हिस्सा निहित हो चुका है। इसलिए प्रार्थीया प्रार्थना-पत्र की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रश्नगत भूमि प्रार्थीया की माता अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया की माता अप्रार्थी सं० 1 जो कि लगभग 82 वर्ष की वृद्ध महिला है तथा अक्सर बीमार रहती है और अप्रार्थी सं० 2 ने प्रार्थीया की माता को बंधक बना रखा है। अब वह प्रार्थीया की माता अप्रार्थीया सं० 1 को अपने चुंगल में लेकर प्रार्थीया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि को हर प्रकार से खुरद बुर्द रहन बैय करने पर आमादा है। यदि वह अपने मनसूबों में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमय क्षति होगी इसलिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया जावे। अप्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को अस्वीकार किया एवं वादग्रस्त भूमि को स्वअर्जित भूमि होने का कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीया का प्रार्थना-पत्र अपीलान्धीन निर्णय के द्वारा खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्षकी बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि, वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट व उसकी बहनों का कब्जा मुताबिक घरा

lomo  
राजस्व अपील प्राधिकार  
हनुमानगढ़

घरू बंटवारा है। उक्त तथ्य अपील में प्रस्तुत दस्तावेज जल संसाधन विभाग की रसीद वर्ष 2019 व 2020 जो अपीलाण्ट के नाम है व दस्तबरदारी दिनांक 19.04.2010 जो अपीलाण्ट व उसकी बहन उर्मिला, सुमन व संतोष द्वारा अपने भाई अशोक कुमार व बहन विमला के पक्ष में निष्पादित की है से यह साबित है कि पक्षकारों के मध्य घराघरू बंटवारा समझौता हुआ था। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रथीया के पक्ष में है। वादग्रस्त भूमि स्व० पृथ्वीराज के सेवा निवृत्त होने पर प्राप्त राशि व कृषि भूमि की आय से खरीद की गई थी। रेस्पोंडेण्ट प्रार्थीया को बेदखल करने व भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करके प्रार्थीया को बेदखल करने भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने व रहन बैय करने पर उतारू है। आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रर्थना-पत्र स्वीकार किया जावे। आरआरटी 2014 (II) पेज 1165 यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय में लम्बित कोई कार्यवाही की नकल या प्रकरण से सम्बन्धित कोई दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लिया है तो उसे रिकार्ड पर लेना चाहिए। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जायदाद है जिसमें किस पक्ष का कितना हक हिस्सा है यह विचाराधीन वाद में साक्ष्य के उपरान्त ही निर्धारित हो सकता है। ऐसे में भूमि की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए। आरबीजे 2009 पेज 409 संयुक्त परिवार की भूमि में पुत्र पुत्री का जन्म से हिस्सा होता है इसलिए वाद के निर्णय तक रहन बैय से रोका जाना विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2012 पेज 26, आरबीजे 2006 पेज 405, आरबीजे 2015 पेज 299, आआरटी 2007 (II) पेज 813, डीएनजे 2021 (रेव) पेज 997, आरआरटी 2014 (II) पेज 1165, आरआरटी 2019 (I) पेज 619 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने तमाम तथ्य निराधार व झूठे अंकित किये हैं। रेसपोडेण्ट नीमा देवी शारीरिक व मानसिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ है व अपना भला बुरा समझने में स्वयंम सक्षम है। प्रश्नगत भूमि रेसपोडेण्ट की खरीद शुदा भूमि है एवं खरीद के समय से ही कब्जा काशत चली आ रही है व अपने कब्जा काशत में स्वयं अर्जित भूमि की पूर्ण स्वामी है, जिसे रहन बैय अन्तरण करने का रेस्पोंडेण्ट को पूर्ण अधिकार है। अपीलाण्ट के पक्ष में किसी

*Leop*

राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़



प्रकार से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन नहीं बनता है एवं अपूर्ण्य क्षति का बिन्दू भी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है। अपीलान्ट का आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज अपील स्तर पर ग्राह्य नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलान्ट द्वारा अपील में प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियां होने हैं। आरआरटी 2014 (II) पेज 1165 के अनुसार यदि प्रकरण से संबंधित न्यायालय में लंबित कार्यवाही की नकल या प्रकरण से सम्बन्धित कोई दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो उसे रिकार्ड पर लेना चाहिए। प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रमाणित दस्तावेज है एवं प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किये गये हैं, जो अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेज हैं। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेजात को अभिलेख पर लिया जाता है।

जहां तक अपील के गुणावगुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि रेस्पोजेण्ट नीमा देवी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। अपीलान्ट ने जिसे संयुक्त परिवार की मेहनत व श्रम से अर्जित होना बताते हुए अपना हक हिस्सा होना बताया है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त परिवार की जायदाद है या नहीं जिसमें किस पक्षकार का कितना हक हिस्सा है ये तथ्य साक्ष्य के बाद वाद में निर्धारित होना है और वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। आरबीजे 2019 पेज 299 में यह अभिनिर्धारित किया है कि वाद की बहुलता को राकने हेतु वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि को रहन बैय से रोकना आवश्यक है साथ ही आरआरटी 2007 पेज 813 के अनुसार पैतृक भूमि में सभी सह दायिकों का हिस्सा है, अधिकारों के निस्तारण हे वाद लम्बित है इसलिए रहन बैय करने से रोका जाना विधि सम्मत है एवं डीएनजे 2021 II पेज 997 के अनुसार न्यायालय का यह दायित्व/कर्तव्य है कि वाद के निर्णय तक वादग्रस्त सम्पति की सुरक्षा की जावे। उपरोक्त तथ्यों न्यायिक दृष्टान्तों के अलौक में चूंकि उभयपक्ष के मध्य प्रश्नगत भूमि में हक अधिकारों को लेकर विवाद है, जिसका निर्धारण मूल वाद में ही होना है, उभयपक्ष के हक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एवं वाद की



*Law*

राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़

बहुलता को रोकने के लिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर पीलीबंगा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2021 निरस्त किया जाता है एवं अपीलांट का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि रेस्पोंडेंट सं० 1 निमा देवी के नाम दर्ज चक 5 टी.के.डब्ल्यू, खाता सं० 30 प. नं. 4/220 किला नं. 1 ता 20, 22 ता 25 की कुल 6.009 है० भूमि में से 100 हिस्सा यानि 5 बीघा भूमि को ता फैसला वाद किसी भी तरह से रहन बैय या मुक्तकिल न करे व मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 23.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Handwritten signature: Karan Singh Puniya*  
(करतारसिंह पूनिया)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
हनुमानगढ़